

Daily Current Affairs 22/07/2021

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने राज्यसभा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के बारे में जानकारी दी।
- NHM समर्थित स्वास्थ्य प्रणाली

में सुधारों के परिणामस्वरूप लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों का विकास हुआ है।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के बारे में:

- NHM को भारत सरकार द्वारा 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) (2005 में शुरू किया गया) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) (2013 में शुरू किया गया) को मिलाकर शुरू किया गया था।
- **NHM सहायता** राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मानदंडों के अनुसार नई सुविधाओं की स्थापना और मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन के लिए उनकी आवश्यकता के आधार पर बुनियादी ढांचे के अंतराल को कम करने के लिए प्रदान की जाती है।
- **NHM सहायता** मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, और तपेदिक जैसी प्रमुख बीमारियों, डेंगू, मलेरिया और कुष्ठ रोग जैसे वेक्टर जनित रोगों आदि से संबंधित कई मुफ्त सेवाओं के प्रावधान के लिए भी प्रदान की जाती है।

NHM के तहत समर्थित अन्य प्रमुख पहल:

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
- निःशुल्क दवाओं का क्रियान्वयन और निःशुल्क निदान सेवा पहल
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
- राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचे का कार्यान्वयन (सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में)

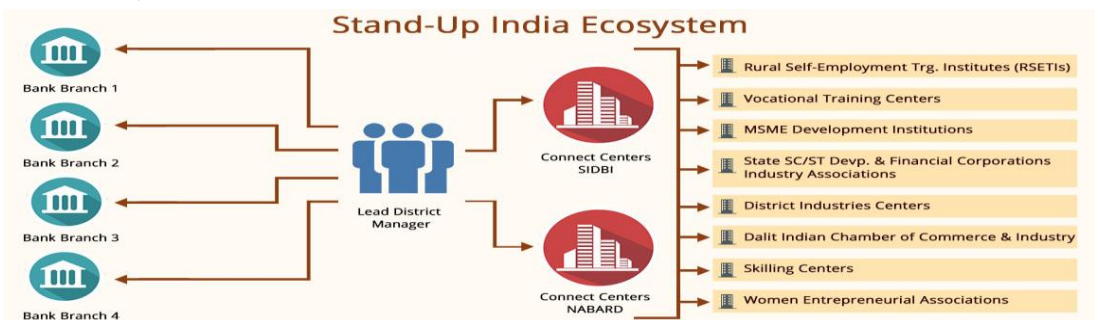
- मोबाइल मेडिकल यूनिट और टेली-परामर्श सेवाएं (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए लागू)
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
- आयुष्मान भारत

NHM की उपलब्धियां

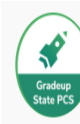
- कार्यान्वयन के 15 वर्षों में, NHM ने स्वास्थ्य के लिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (MDG) की उपलब्धि को सक्षम किया है।
- इससे मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य संकेतकों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- समान विकास: आदिवासी आबादी, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में रहने वालों और शहरी गरीबों के स्वास्थ्य पर भी निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि: NHM स्वास्थ्य प्रणाली के दृष्टिकोण को अपनाता है और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखता है।
- राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं
- मानव संसाधन वृद्धि: NHM डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे सेवा वितरण HR को शामिल करने के लिए राज्यों का समर्थन करता है और आशा (ASHA) के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यक्रम को भी लागू करता है।
- उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE): OOPE के वर्तमान उच्च स्तर को कम करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए यह कहा गया कि OOPE का लगभग 70% हिस्सा दवाओं और निदान के कारण है, NHM के तहत मुफ्त दवाएँ और निःशुल्क नैदानिक सेवा संबंधी पहल लागू की गई है।

स्रोत: PIB

2. स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ाया गया



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



चर्चा में क्यों?

- वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय ने बताया कि स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में:

- यह योजना 05 अप्रैल, 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गयी थी।

उद्देश्य और ऋण की प्रकृति:

- इस योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा में कम-से-कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम-से-कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है।
- यह उद्यम विनिर्माण, सेवाओं, कृषि-संबद्ध गतिविधियों या व्यापारिक क्षेत्र में हो सकता है।
- गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में, 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।
- SIDBI और NABARD के कार्यालय स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटर (SUCC) नामित हैं।

नया परिवर्तन:

- FY 2021-22 के लिए, योजना के तहत ऋण के लिए मार्जिन मनी की आवश्यकता '25% तक' से घटाकर '15% तक' कर दी गई है और कृषि से जुड़ी गतिविधियों को योजना में शामिल किया गया है।

प्रदर्शन:

- 28.06.2021 को 26204.49 करोड़ रुपये के कुल 1,16,266 ऋण योजना के तहत शुरुआत से ही बढ़ाए जा चुके हैं।

स्रोत: PIB



3. पंजाब SOHUM (AABR) शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना



चर्चा में क्यों?

- पंजाब सरकार ने यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत SOHUM-ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रिस्पॉंस सिस्टम (AABR) की शुरुआत की।
- पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने सोहम (AABR) की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

- यह पहल नवजात और छोटे बच्चों में श्रवण हानि की प्रभावी रूप से जांच करेगी।
- यह उपकरण निश्चित रूप से प्रभावी

मूल्यांकन और समय पर ढंग से श्रवण हानि के प्रबंधन में मदद करेगा।

नोट:

- भारत जैसे विकासशील देश में प्रति हजार 5-6 बच्चे इस दोष के साथ पैदा होते हैं।
- भारत में लगभग 63 मिलियन लोग श्रवण दोष और संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं।

SOHUM के बारे में:

- यह स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायोडिजाइन स्टार्ट-अप SOHUM इनोवेशन लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित एक स्वदेशी रूप से विकसित नवजात श्रवण स्क्रीनिंग डिवाइस है।
- इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत विकसित किया गया था।

स्रोत: TOI



4. DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश-NG का सफल परीक्षण किया



चर्चा में क्यों?

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के तट के करीब एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा में मार करने वाली नई

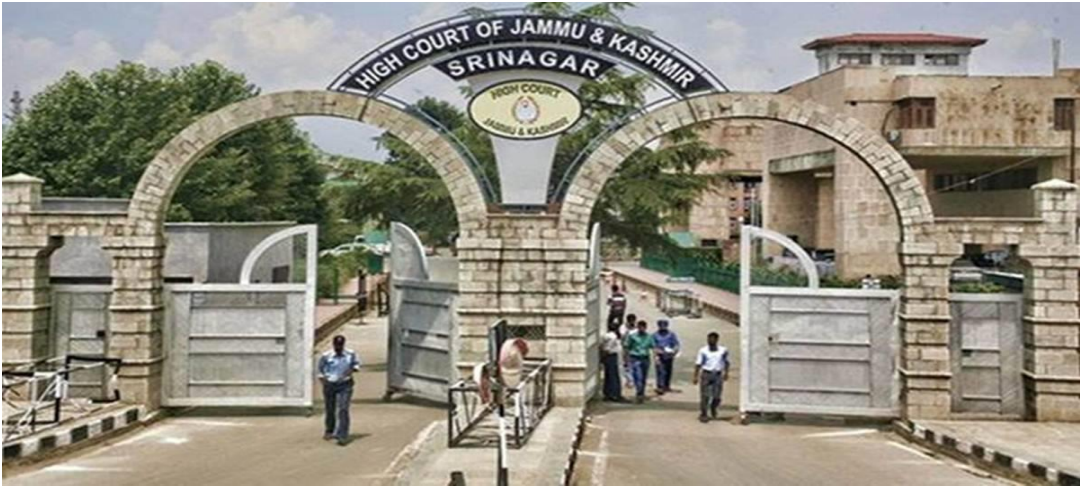
पीढ़ी आकाश मिसाइल (आकाश-NG) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

प्रमुख बिंदु

- मिसाइल प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL), हैदराबाद द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है।
- परीक्षण के दौरान, मिसाइल ने तेज और फुर्तीले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए आवश्यक उच्चस्तरीय गतिशीलता का प्रदर्शन किया।

स्रोत: PIB

5. 'केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय' का नाम 'जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय' किया गया



Follow us on
Telegram



Gradeup
PCS & Other
State Exams



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



- लंबे समय तक चलने वाले और बोझिल' नामकरण 'केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय' को 'जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय' में बदल दिया गया है।
- कानून और न्याय मंत्रालय में न्याय विभाग द्वारा आदेश को अधिसूचित किया गया था।
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव को प्रभावी करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2021 पर हस्ताक्षर किये हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

6. दो भारतीय संगठनों ने UNDP इक्वेटर पुरस्कार 2021 जीता



चर्चा में क्यों?

- जैव विविधता हानि और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थानीय, अभिनव, प्रकृति-आधारित समाधानों को प्रदर्शित करने में उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए दो भारतीय संगठनों ने प्रतिष्ठित UNDP इक्वेटर पुरस्कार 2021 प्राप्त किया।

प्रमुख बिंदु

- विश्व स्तर पर दस विजेताओं में से भारत की ओर से दो संगठन हैं- अधिमलाई पझंगुडियनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेहकुंजा ट्रस्ट।
- उनमें से प्रत्येक को 10,000 अमरीकी डालर का पुरस्कार और इस वर्ष के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा, द नेचर फॉर लाइफ हब और UN फूड सिस्टम्स समिट से जुड़े विशेष आभासी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

अधिमलाई पझंगुडियनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बारे में:

- दक्षिण भारत में नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व के स्वदेशी लोगों द्वारा प्रबंधित और पूरी तरह से संचालित इस 1,700 सदस्यीय सहकारी ने वन उत्पादों और फसलों की विविध श्रेणी के प्रसंस्करण और विपणन द्वारा 147 गांवों में आजीविका में सुधार किया है।



Follow us on
Telegram



Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers

Subscribe Now



स्नेहकुंजा ट्रस्ट के बारे में:

- स्नेहकुंजा ट्रस्ट ने 45 वर्षों के लिए पश्चिमी घाट और कर्नाटक तट में संवेदनशील आर्द्रभूमि और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की है। स्नेहकुंजा ट्रस्ट भारत में वर्तमान में पहली ब्लू कार्बन परियोजना का संचालन कर रहा है।

इक्वेटर पुरस्कार के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत इक्वेटर इनिशिएटिव द्वारा आयोजित इक्वेटर पुरस्कार, जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के माध्यम से गरीबी को कम करने के लिए उत्कृष्ट सामुदायिक प्रयासों को मान्यता देने के लिए द्विवार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है।

स्रोत: undp.org

gradeup